the Government and the people of India is that we want friendly, good-neighbourly and friction-free relations.

MR. CHAIRMAN: Kindly continue to try for it. Now, Question No. 22.

Postponement of the meeting of Foreign Ministers of SAARC

*22. SHRI HARI SINGH: †
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of the Foreign Ministers of the South Asian Association for Regional Cooperation which was to be held on 28th June, 1989 in Islamamabad, Pakistan has been postponed;

(b) if so, what was the cause of the postponement of the above meeting; and

(c) what is the reaction of the Government of India in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) The seventh session of the SAARC Council of Ministers, scheduled to have been held on July 1-2, 1989 in Islamabad was postponed consequent to Sri Lanka informing the host country Pakistan of its decision not to participate in the meeting. Since the Council of Ministers would not have been able to take any decisions in the absence of any single member country, this meeting was postponed to a date to be decided after mutual consultations between all the member States.

(c) India is disappointed at the postponement of the meeting and views it as a setback to the process of regional cooperation.

श्री हरी सिंह : : मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रीलंका ने अपने पत्र में जो कारण लिखे हैं हिस्सा न लेने के लिए, वह कारण क्या हैं ?

दूसरे, जो वर्तमान परिस्थितियों में श्रीलंका भारत के जो संबंध हैं उनको देखते हुए क्या जो सार्क की मीटिंग होने वाली है उसके संविधान में क्या ऐसा भी है कि यदि कोई भी मैंबर पार्टिसिपेट करने में विवश हो तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा दूसरा पड़ोसी राष्ट्र जो उसका सदस्य है वह बदली हुई परिस्थिति में उपस्थित होने में मजबूर हो तो क्या सार्क का जो हमारा यह संगठन है, यह फेल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा ?

श्री नटवर सिंह : सभापति महोदय, सार्क के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी दो-तरफा सवाल नहीं उठाया जाएगा चाहे वह भारत-श्रीलंका के बीच का हो, श्रीलंका -मालदीव के बीच का हो या नेपाल-बंगला देश का हो, वह सवाल नहीं उठाया जाएगा । दूसरी बात वह लिखी हुई है कि कोई भी मीटिंग हो चाहे फारेन मिनिस्टर्स की हो या प्रधान मंत्रियों की हो या राष्ट्रपतियों की हो, अगर उसमें से एक भी मेम्बर नहीं आएगा तो बैठक नहीं हो सकेगी । अगर उसमें से एक मम्बर नहीं आयेगा तो वह बैठक नहीं हो सकती । उन्होंने यह पत्र लिख दिया 24 जून को । उसकी सदारत कर रहे थे पाकिस्तान के वजीर-ए खारजा, विदेश मंत्री यादव खां । उन्होंने लिखा सभापति जी हम नहीं आ पायेंगे क्योंकि, इस वक्त हिन्दुस्तान की आई०पी०के० एफ० श्रीलंका में है । यह सवाल श्रीलंका

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Hari Singh.

तीन बार उठा चुका है। दिल्ली में बैठक हुई थी दो साल पहले फोरेन मिनिस्टर्स की तब भी यह सवाल आया था और तब वह मीटिंग करने आ गये थे। थिम्पु में मीटिंग हुई वहां भी सवाल उठा। अब इस्लामाबाद होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आयेंगे। इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी। हम तो जाने के लिए तैयार थे। हमारे फोरेन सेक्रेटरी वहां पहुंच चुके थे और नरसिंह राव जी जाने को तैयार थे। जब श्रीलंका की सरकार ने यह खत भेज दिया कि वह नहीं आयेंगे तो यह बैठक नहीं हो सकी।

श्री हरी सिंह : माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि इसका संविधान खुद इसकी कार्रवाई में एक रोड़ा बन गया है। जब इसमें आपसी सम्बन्ध उठने का सवाल नहीं है तो पड़ोसी देशों में आपस में कुछ न कुछ मुद्दों पर सवाल उठते रहे हैं तो इस सार्क की कभी मीटिंग होने का सवाल ही नहीं होगा। ऐसी हालत में क्या संविधान में सुधार करने पर विचार होगा ? क्या सरकार अपनी तरफ से कोई सुधार रखेगी ?

श्री के० नटवर सिंह : आपने जो सवाल पूछा है वह अहमियत का सवाल है, गम्भीर सवाल है। जब सार्क बना था उसमें यह था तिजारत के बारे में, मौसम के बारे में, खुराक के बारे में, हेल्थ के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, प्लानिंग के बारे में और गैर राजनीतिक मामलों पर बातचीत हो सकती है और कुछ कामयाबी और सफलता भी पायी है हमने पिछले तीन-चार सालों में। जो समस्यायें हैं सार्क के देशों की वह एक सी करीब-करीब है। भारत वर्ष एक ऐसा देश है जिसके बार्डर सार्क की दृष्टि से सब की सीमा से मिलते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है। पहले यह फैसला किया गया था ऐतिहासिक कारणों की वजह से जो तनाव है दो तरफा, राजनीतिक सवालों पर अगर बातचीत होगी तो यह बिस्मिल्ला गलत होगा। यह निर्णय लिया गया कि पहले इकोनोमिक सवालों पर, ट्रेड के सवालों पर, पालिटिकल सवालों पर बातचीत की जाए। सफलता मिल रही थी। मैं जानता हूं तनाव तो है आपस के अन्दर। यूरोप में दो सौ, तीन सौ साल लगे ऐसा बनाने के लिए। मैं नहीं कहता कि 200-300 साल लगेंगे। मगर कुछ समय लगेगा जब तक राजनीतिक तनाव कम नहीं होंगे। हम चाहते हैं और पहलुओं पर तरक्की हो, बातचीत हो, दो तरफा हो, सार्क के बारे में हो, आसिअन में क्या करना चाहिए, रेल के लिए क्या करना चाहिए ? कामन पासपोर्ट हो सकता है ? बहुत सी बातें हो रही थीं। सिर्फ श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने बार-बार यह बात उठायी कि हम राजनीतिक मामलों पर बहस करेंगे। जब यह संविधान बनाया गया था तो सब ने यह ख्याल किया था कि अगर राजनीतिक मामले इसमें आयेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बड़े अफसोस की बात है, हम भारी दिल से यह कहना चाहते हैं कि यह सवाल सार्क की मीटिंग के एजेंडे में कैसे आ सकता है। सवाल है हिन्दुस्तान और श्रीलंका में बात चीत होनी चाहिए। सार्क में कोई फैसला नहीं हो सकता। हम यह चाहते हैं कि अगर इन सवालों को उठायेंगे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी। आपने जो कहा दुरुस्त बात है। हम यह चाहते हैं सार्क आगे बढ़े क्योंकि इस सारे रीजन के लिए, एरिया के लिए वह बहुत कुछ कर सकती है और गैर राजनीतिक और गैर सियासी मामलों पर।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्रीलंका की हठधर्मी की वजह से भारत श्रीलंका से अपनी शांति सेना को हटा ले इस कारण क्यों दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक स्थगित करनी पड़ी। 27 जून की खबर है 'Lanka firm on boycott. India condemns attempt to disrupt SAARC functioning.' 29 जून की खबर है कि सार्क आफिशियल टू विजिट श्रीलंका। उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि दक्षिण एशिया के 6 विदेश मंत्रियों ने 29 जून को इस्लामाबाद में फैसला किया कि सार्क

के सेक्रेटरी जनरल अबुल एहसान को श्रीलंका भेजा जाए कि वह श्रीलंका से कहे कि वह सार्क की आगामी बैठक में शामिल हो, इसके लिए राजी करे। तो क्या बातचीत हुई है अबुल एहसान से इस बातचीत का विवरण मैं जानना चाहता हूं। क्या परिणाम निकले यह भी जानना चाहता हूं। अभी हमारे भारत के प्रधान मंत्री और हमारे नेता माननीय राजीव जी पाकिस्तान गये थे और उस समय पाकिस्तान की प्रधान मंत्री और सार्क की अध्यक्ष बेगम बेनजीर भुट्टो से उनकी बातचीत हुई सार्क के सम्मेलन के सम्बन्ध में, यह जानना चाहता हूं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री के. नटवर सिंह : सभापति महोदय, पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इसके ऊपर बयान दिया जाएगा और अगर आप चाहते हैं और आनरेबल मेम्बर्स की ख्वाहिश है, तो इस सवाल पर बहस हो सकती है, डिसकशन हो सकता है और जो सारी चीजें हैं वे आपके सामने रख दी जायेंगी। जहां तक आपके सवाल का जवाब है, वह यह है कि ... **(व्यवधान)**

डा. रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी चाहते हैं तो मैं मांग करता हूं कि इस पर बहस की जाय।

श्री कपिल वर्मा : इस बारे में एक मोशन तो आपके यहां आलरेडी एडमिट है।

श्री सभापति : आपका जो बयान है वह क्या प्राइम मिनिस्टर के विजिट पर होगा ?

श्री के. नटवर सिंह : श्रीलंका पर बातचीत हो सकती है, खुशी से हो सकती है। जहां तक आपने जो सवाल किया है ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्यों सार्क पर नहीं ? आज शाम को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में बात कर लेंगे।

श्री के० नटवर सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके सेक्रेटरी जनरल, सार्क के श्री अहसान साब दौरा लगाने वाले थे, लेकिन मेरे ख्याल में वे अभी श्रीलंका गये नहीं हैं। उन्होंने तारीख मांगी है कि वे वहां कब आ सकते हैं। जहां तक प्रधान मंत्री की बातचीत का सवाल है पाकिस्तान के वजीरे आजम के साथ, इसके बारे में बात जरूर हुई थी, लेकिन जो बात हुई थी, मैं उसको आपके सामने नहीं रख सकता। मगर यह जरूर मालूम है कि पाकिस्तान सरकार ने कुछ अपने जजबात का इजहार श्रीलंका की सरकार के सामने रखे हैं कि अगर उनको 24 जून को होने वाली सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं आना था तो पहले खबर क्यों नहीं कर दी। पाकिस्तान के लिए तो यह इम्बैरसमेंट की बात है कि सब लोग तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक देश नहीं है। पहले बता देते तो इस बैठक को रखते ही नहीं। इस पर बातचीत हुई थी। मैं भी अभी कल ही, जाकार्ता में वहां के मंत्री आये थे, उनसे बातचीत हुई। श्री नरसिंह राव जी की भी वहां के विदेश मंत्री से बात हुई। जब इस पर आधे घंटे की बहस होगी तो जो सारा नक्शा है, हमारा रिश्ता श्रीलंका के साथ है, वह आपके सामने रखा जाएगा।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : बातचीत का रूप क्या है, कम से कम इसकी ओर तो इशारा कर सकते हैं।

श्री सभापति : उन्होंने बताया है कि वे इस पोजीशन में नहीं है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत को बता सकें।

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: Sir, this matter cannot be fully gone into satisfactorily through questions and answers....

MR. CHAIRMAN : He has agreed to the request for a discussion.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: I request the Minister to give a Background Paper to us on the various developments regarding

SAARC. And having said that, Sir, since he concedes that the Regional Cooperation is a very important and vital matter and SAARC is still in its infancy and already it is paralysed because of the boycott of Sri Lanka from the meeting in Islamabad, may I know from him whether there is any future for SAARC and what efforts are being made by various members of the SAARC community to sort out the differences? He has very well said that bilateral relations should not be discussed. It is accepted by all. Still it is being raised by one Member and there is no guarantee that such things will not be raised again in future. What efforts are being made by the Members of SAARC to sort out these differences in the very infancy and to see that SAARC is built on a sound foundation?

SHRI K. NATWAR SINGH: Sir, all I can say is that all Members of SAARC naturally are concerned about this development. So far, there were no postponements of meetings because of this. When there was the reluctance of the Government of Sri Lanka to participate in meetings of Foreign Ministers in 1987 and earlier, we were able to patch up the differences and persuade them to come. Now, with the new dispensation, after the recent elections in Sri Lanka, we find a hardening of Sri Lankan attitude on a variety of matters, which of course we will go into when the House discusses this matter. But all members of SAARC, and I know the Government of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the Foreign Minister, are exercised over this because Pakistan is the Chairperson of SAARC for the current year. If after consultations—informally, I have discussed this matter with His Majesty the King of Bhutan when he was here, so did the Prime Minister and others—this is worrying...

MR. CHAIRMAN: You are trying all that you can.

SHRI K. NATWAR SINGH: In a world where differences are being reduced, where tensions are being reduced, where there is an air of goodwill, of understanding, of co-operation and not of conflict and confrontation, it is a matter of deep regret that in our region, an organisation which is only 5 or 6 years old, should have met this hurdle so early in its life. It will be our endeavour as diplomats and well-wishers to see that these differences are reduced to a minimum, and if I may respectfully say so, there is a very mistaken but very widespread impression that the practice of diplomacy and formulation of foreign policy are an easy exercise. Even most modest progress deserves profound respect. And, therefore, a great deal of patience, understanding, goodwill and lot of hard work will be required by all members and we are doing all we can. But it will be a matter of very great regret if as a consequence of intransigence of a particular government, the whole organisation is allowed to die prematurely.

SHRI SUKOMAL SEN: Because Sri Lanka boycotted SAARC on the bilateral issue of IPKF withdrawal from Sri Lanka, I understand Bangladesh Foreign Secretary visited Sri Lanka to persuade Sri Lankan Government not to raise bilateral issues in SAARC meeting and also to join the SAARC session. I would like to know whether Bangladesh has since informed India about the results of the talk between their Foreign Secretary and Sri Lanka Government and whether there is a positive result.

SHRI K. NATWAR SINGH: The Foreign Minister of Bangladesh was here and he met Shri Narasimha Rao on the 7th of July and discussed this matter. But we have not been able to resolve the problem. The problem exists because attitude of the Government of Sri Lanka is not particularly helpful.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Negotiation for purchase of 19-seater aircraft by Vayudoot

*23. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Vayudoot is negotiating with a Czechoslovak firm and a Polish firm for the purchase of 19-seater aircraft; and

(b) if so, what are the reasons that Vayudoot is not going for Dornier aircraft which is being produced in India by H.A.L.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) Apart from the HAL manufactured Dornier-228, M/s Vayudoot is examining other aircraft of about 20 seat capacity from rupee trade areas including Poland and Czechoslovakia. The inhouse techno-economic evaluation has not reached the negotiation stage.

SHRI SURESH KALMADI: The hon. Minister in his reply has stated that apart from HAL manufacturing Dornier—228, they are considering Czech. aircraft and Polish aircraft. I do not think this is a fact. As per my information, they are not considering the Indian manufactured aircraft at all for the expansion of the Vayudoot fleet. Sir, the Vayudoot feels that Dornier is a bad aircraft. It has reason to because there have been over 50 engine failures on the Dornier. But it has to be examined as to why there were so many engine failures, because all over the world, Dornier is a good aircraft. So many airlines all over the world are flying it very well. Why this problem only in India? Why is it that Vayudoot has not been able to utilise Dornier properly? It is because of bad maintenance; it is because of overflogging of the aircraft; it is because Vayudoot aircraft is flogged 30 per cent more than it should be; maintenance is bad and we are increasing routes. We have already crossed 100 centres. Everybody going and asking for one more route is getting one more, and that is the reason that Dornier has proved unsuccessful in the country. And definitely now, when it comes to expansion phase, I do not know why Dornier is not considered because Government of India after appointing numerous committees, had decided to manufacture Dornier in the country and HAL is manufacturing it. Why is it that Vayudoot is not going in for the Dornier? We are manufacturing it in India. You say that the price is high. But if you give orders, if the Coast Guard and other people give orders, the price would come down. We should use the Dornier properly. I would like to have an assurance from the hon. Minister that Vayudoot would consider Dornier which is being manufactured by the H.A.L. with German collaboration instead of going in for others. would that assurance be given? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Would you consider the Dornier for the Vayudoot? He wants an assurance.

SHRI SHIVRAJ PATIL: I have understood the question and I would like to reply. The price of one Dornier is Rs. 6·33 crores and the price of one AN-22 aircraft from Poland, which is being examined by us, is only Rs. 2 and odd crores. The price difference is very big. Moreover, the Dornier is manufactured in India but the components are not manufactured in India. All the components have to be imported. When we import the components from the hard currency areas, we have to spend foreign exchange. These are the two very important considerations.